कालीन निर्यात संवर्धन परिषद्
CARPET EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Set up by Ministry of Textiles, Govt. of India)
Working Office : 2nd Floor, Rajiv Gandhi Handicrafts Bhawan, Baba Kharak Singh Marg, New Delhi – 110001
Phone : +91-11-233 647 16, 233 64717
E-mail : info@cepc.co.in, **Website :** www.cepc.co.in
Regd. Office : Shreejee Complex, Shop No. T-3, Sharma Market, Harola, Noida (U.P)
Website of Ministry of Textiles : www.texmin.nic.in

प्रैस विज्ञप्ति

दिनांक : 03-12-2020

वाणिज्य विभाग, भारत सरकार मौजूदा मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव (MAI) योजना को अद्यतन / मूल्यांकन करने की प्रक्रिया मे हैं और इस संबंध में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (IIFT) MAI योजना के मूल्यांकन के लिए लगा हुआ है। आज, 3 दिसंबर, 2020 सीईपीसी ने प्रमुख सदस्य-निर्यातकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक बुलाई।

बैठक में प्रो. राकेश मोहन जोशी, परियोजना परिवीक्षक और डॉ. पूजा लखनपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, आईआईएफटी ने भाग लिया।

श्री सिद्ध नाथ सिंह, अध्यक्ष, कालीन निर्यात संवर्धन परिषद, श्री उमेर हमीद, द्वितीय उपाध्यक्ष, श्री उमेश कुमार गुप्ता, श्री संदीप कटारिया, श्री हुसैन जाफर हुसैनी, श्री संजय गुप्ता, प्रशासनिक समिति के सदस्य, और श्री संजय कुमार, अधिशासी निदेशक, सीईपीसी ने बैठक में भाग लिया।

कालीन उद्योग से प्रमुख प्रतिनिधि श्री विनय कपूर, श्री असलम महबूब, श्री राजकुमार बोथरा, श्री वी.पी. गुप्ता, श्रीमति अल्पा मेवालाला भी बैठक में उपस्थित थे ।

श्री सिद्ध नाथ सिंह, अध्यक्ष, कालीन निर्यात संवर्धन परिषद ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में उल्लेख किया कि कोविड -19 के बाद व्यापार परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया है और हमें उद्योगो को आगे बढ़ाने के लिए आभासी और भौतिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। श्री सिद्ध नाथ सिंह ने उल्लेख किया कि हस्तनिर्मित कालीन उद्योग ग्रामीण आधारित, कुटीर उद्योग है जो अत्यधिक श्रम गहन है और विशेष प्रकृति के कारण कालीन उद्योग की आवश्यकताए संक्षेप में निम्न प्रस्तुत की गयी हैं :

1. भारत से 50% से 55% निर्यात अमेरिका को होता हैं और 30% से 35% तक यूरोप को और बाकी दुनिया को 15% । खरीदारों को आतिथ्य प्रदान करने के लिए विकसित और गैर-विकास वाले देशों के प्रतिबंध को हटाना चाहिए ।

2. विदेशी गतिविधियों में सदस्यों की भागीदारी की सीमा को 3 बार से बढ़ाकर 5 बार तक करना चाहिए ।

3. सदस्य-निर्यातकों को विदेशी प्रचार के वर्तमान अनुदान को 5% से बढ़ाकर 20% करना चाहिए ।

4. छोटे बीएसएम और प्रदर्शनियों में न्यूनतम भागीदारी 50 से घटाकर 10 करने का विचार करना चाहिए ।

5. सरकार को नए बाजारों की क्षमता का मूल्यांकन और अन्वेषण के लिए 3 से 5 सदस्यों वाले छोटे प्रतिनिधि मण्डल को विदेश भेजने के लिए उद्योग का समर्थन करना चाहिए ।

कुछ सदस्यों ने निम्नलिखित अनुरोध किऐ -

- विदेशी बाजार में उपभोक्ताओं को विनिर्माण प्रक्रिया पर विस्तृत वृत्तचित्र तैयार करने और विदेशी बाजार में इसका प्रसारण के लिए विशेष धन का प्रबंध ।

- प्रदर्शनी वस्तुओं के भाड़े पर अनुदान / सब्सिडी ।

- ई-कॉमर्स पर अनुदान / सब्सिडी।

प्रो. राकेश मोहन जोशी, प्रोजेक्ट लीडर और डॉ. पूजा लखनपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, आईआईएफटी ने सदस्यों से अनुरोध किया कि वे जल्द से जल्द प्रश्नावली में अपने सुझाव प्रस्तुत करें ताकि वे अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप सकें।

श्री सिद्ध नाथ सिंह ने आगे ॥CT भदोही में परीक्षण सुविधाओं पर परिषद को सुझाव देने और नई 5 वर्षीय विदेश व्यापार नीति के लिए सुझाव देने के लिए सदस्यों से समर्थन और सहयोग का अनुरोध किया।

****